Title: Need to refund investors' money by P.A.C.L, a Pearl Group Company as per the orders of the Supreme Court.

भी तस्वन ताल साढ़ू (बिलासपुर)ः भारत वर्ष में सन 1983 से काम कर रही पर्ल्य समूह की 1996 में शुरू हुई पी.ए.सी.एल. तिमिटेड रियल स्टेट में भूखंड देने के नाम पर देश भर में किशत भुगतान एवं एकमुश्त योजनाएं वला रही थी जिसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के एम.सी.ए. एवं डी.एस.ए. डिपार्टमेंट में हैं। उक्त कंपनी के वेयरमैन निर्मल सिंह भंगु हैं। पी.ए.सी.एल. तिमिटेड में देशभर के 6 करोड़ निवेशकों का 49,100 करोड़ रूपये जमा है।

इस पर 2012-13 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं सी.बी.आई. के द्वारा इसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्निवन्ह लगाते हुए इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। इस दौरान इस कंपनी के पास 1,85,000 करोड़ की संपत्ति पूरे भारत देश में हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सर्वोद्य न्यायालय ने छः माह के अंदर निवेशकों का पैसा फरवरी, 2016 तक वापस किया जाए, का आदेश दिया एवं रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट आर.एम. लोहा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और कहा कि कंपनी की सभी संपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जाए।

किन्तु आज 7 माह बीत जाने के बाद भी सेबी एवं लोढ़ा कमेटी के द्वारा पैसा देना प्रारंभ नहीं किया गया हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बिलासपुर के कोटा विधान सभा क्षेत्र से 10,000 से ज्यादा लोग निवेशक हैं जिनका 18 करोड़ रूपये निवेश उक्त कंपनी ने कराया हैं। इस मामले से आर.एन. लोढ़ा समिति को अतिशीधू अवगत कराये जाने की आवश्यकता हैं।